

आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक-23 जून 2024

7:20 AM

- जीएसटी के फर्जी चालान को रोकने के लिए केंद्र सरकार शुरू करेगी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था, रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गयी कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से किया गया बाहर ।
- प्रदीप खरोला बनाये गये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए के नये अध्यक्ष, नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच करेगी सीबीआई ।
- प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा, कहा- मेटेनेंस की वजह से बिजली कटे तो सोशल मीडिया के जरिये दी जाए सूचना ।
- कल से शुरू हो रहा है अटारहवीं लोकसभा का पहला सत्र, छब्बीस जून को होगा नये लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ।

वस्तु और सेवा कर-जीएसटी परिषद ने स्टील, लोहा और एल्युमिनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में घोषणा की कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही कई सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी मुकदमे कम करने के उद्देश्य से परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार के स्थान पर प्रदीप खरोला अब इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। नीट और यूजीसी नेट की प्रवेश परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों के बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक अन्य अहम फैसला लेते हुए नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही इस वर्ष की संयुक्त सी एस आई आर-यू जी सी-नेट परीक्षा भी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच होनी थी।

इस बीच, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए की परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारु और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति को एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में सुधारों की सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति मौजूदा प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी और वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र का आकलन करेगी। समिति से दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति के गठन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि छात्रों का हित और उज्ज्वल भविष्य हमेशा सरकार की उच्च प्राथमिकता रहेगी।

उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में नई नीति जारी की है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया है कि नई नीति के तहत प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से रोकने और धांधली को खत्म करने के लिये पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस सिलसिले राज्य के सभी आयोगों और बोर्डों को जरूरी दिशा निर्देश भेज दिये गये हैं।

प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में अभिरक्षा में हुई मौत के मामले की जांच कराई जाएगी । साथ ही वहां कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी वहां के एसपी सिटी ने कल संवाददाताओं से बातचीत में दी । जिले में 28 वर्षीय दलित युवक की पुलिस अभिरक्षा में मौत के बाद 21 जून को काफी बवाल हुआ था। इस बीच, प्रशासनिक हस्तक्षेप से युवक के परिजनों ने कल उसका दाह संस्कार कर दिया। परिजनों को प्रशासन के जरिये पांच लाख रुपये का चेक भी प्रदान किया गया । उधर, बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कल अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। संवाददाताओं से बात करते हुए श्री लालपुरा ने कहा कि आयोग धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों और समाजसेवियों के साथ मीटिंग कर उन्हें समय-समय पर न सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देता है, बल्कि उनसे यह अपेक्षा भी करता है कि वे संबंधित जानकारी अल्पसंख्यक वर्ग तक पहुंचाये।

राज्य में कल सोलह आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिये गये हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एस.बी. शिरोडकर की जगह अमरेन्द्र कुमार सेंगर लखनऊ के नये पुलिस आयुक्त बनाये गये हैं, जबकि एस.बी. शिरोडकर को लखनऊ परिक्षेत्र का अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं तरुण गाबा प्रयागराज के पुलिस आयुक्त बनाये गये हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को समय पर त्रुटिहीन बिजली बिल पहुंचाने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने कल लखनऊ में ऊर्जा विभाग की बैठक में अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल जमा कराने के लिये उपभोक्ताओं को जागरूक करने के साथ-साथ वन टाइम सेटलमेंट-ओटीएस के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल की वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी तरह परेशान न किया जाये। उन्होंने बिजली की आपूर्ति में गुणवत्ता पर बल देते हुए कहा कि पिछले पांच साल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में लगे हैं, लेकिन अब क्वालिटी मेंटेन करने पर बल देना चाहिये। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस की वजह से अगर बिजली कटौती की जाती है, तो उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति कब तक बाधित रहेगी, इसकी पूर्व सूचना सोशल मीडिया के जरिये जरूर दी जाये। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर लगाने के काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया।

बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि नोएडा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में बिजली की कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर परियोजना के पहले चरण में राज्य में 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाये जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बिजली आपूर्ति के घंटों में बढ़ोत्तरी की गई है।

देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोक सभा सदस्यों को शपथ दिलायी जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब सदस्यों को शपथ दिलायेंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। यह संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा।

26 जून नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लखनऊ के केजीएमयू में मानसिक रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अमित सिंह ने युवाओं में नशीली दवाओं के सेवन की लत के दुष्प्रभावों के बारे में बताया-

एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नशीली दवाइयों से प्रभावित है। लोग कई बार होता ये है कि अपनी परेशानियों के लिए कुछ नशीली दवाइयाँ लेते हैं, किसी के सुझाव पर या अपनी समझ से। वो जब शुरूआत करते हैं तो उनको उससे कई बार रिलीफ भी मिलता है, लेकिन उस समय में उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि इस दवा से लंबे समय में वह आदी हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो उसके लिए खुद से दवाइयों का सेवन करने से कहीं बेहतर है कि आप डाक्टरों की मदद लें क्योंकि जब डॉक्टर अपनी जानकारी के हिसाब से आपको दवाई देते हैं तो वो इसका ध्यान रखते हैं कि आपको इसकी लत न लगे और इसके दुष्प्रभाव न हों आपको।

भारतीय नागरिक संहिता 2023 के तहत गवाह संरक्षण योजना बनाई गई है। इसके तहत राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना तैयार करने और अधिसूचित करने का अधिकार भी दिया गया है। इसका उद्देश्य आपराधिक आचरण के खिलाफ समाज की रक्षा करना, कानून तोड़ने वालों को रोकना और देश के कानूनों का उल्लंघन करने या इसकी कोशिश करने वालों के अलावा गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें नुकसान से बचाना है।

रामलला बिराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य पुरोहित आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का अंतिम संस्कार कल काशी के मणिकर्णिका घाट पर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
